

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,  
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून, दिनांक ०३ अक्टूबर 2017

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के मानक मद-43 वेतनादि में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-UOU/Fin/2017-18/597/8628, दिनांक 20.09.2017 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के मानक मद-43 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान में प्राविधानित धनराशि रु० 330.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-476/XXIV(6)/2017-42(4)/12 दिनांक 31 मई, 2017 के द्वारा रु० 55.00 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-634/XXIV(6)/2017-42(4)/12, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के द्वारा रु० 175.00 लाख को जोड़ते हुये इस प्रकार कुल धनराशि रु० 230.00 लाख अवमुक्त की गयी, अवशेष धनराशि रु० 100.00 लाख (रु० एक करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न एलोटमेंट आई.डी. संख्या- ११७/८/००४७ के अनुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरण व व्यय करने में वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल पर निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- (4) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- (5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय।

(7) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सूजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

(8) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 07-राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

#### संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
अपर सचिव।

संख्या-७७१ (1)/XXIV(6)/2017/42 (4)/12, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)  
संयुक्त सचिव।